



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आषाढ़ 1945 (श10)

(सं0 पटना 500) पटना, मंगलवार, 27 जून 2023

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

अधिसूचना
21 दिसम्बर 2022

सं0-01/भू0अ0नि0 (5) नियमावली संशोधन (वि0सर्वे0संविदा नियोजन)-05/2022-4672—विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-

- (1) यह नियमावली "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन (संशोधन) नियमावली, 2022" कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-3 के उप नियम-1 (च) एवं (ज) का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली, 2019 के नियम-3 के उप नियम-1 (च) को विलोपित एवं 1 (ज) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(ज) कार्यालय परिचारी (बाह्यस्रोत)”

3. बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-3 के उप नियम-3 का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली, 2019 के नियम-3 के उप नियम-3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(3) कार्यालय परिचारी (बाह्यस्रोत) की सेवाएँ बाह्यस्रोत एजेंसी से तथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवाएँ बेल्ट्रॉन के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी।”

4. बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-3 के उप नियम-4 (ग) का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली, 2019 के नियम-3 के उप नियम-4 (ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त ITI संस्थान से NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय सर्वेयर ट्रेड पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र प्राप्त योग्यताधारी की सेवाएँ अमीन के रूप में प्राप्त की जा सकेंगी”।

5. बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-4 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली, 2019 के नियम-4 के निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“(4) उपरोक्त सभी पदों के लिए उम्र सीमा राज्य सरकार में नियुक्ति के लिए विहित मानदंडों के अनुरूप होगी। उम्र की गणना नियोजन वर्ष के जनवरी माह की प्रथम तिथि से की जाएगी।”

6. बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-6 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली, 2019 के नियम-6 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता।

क्रम संख्या	पदनाम	अर्हता
1	2	3
1	विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	सिविल इंजिनियरिंग में स्नातक +2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव (दो वर्ष का सरकारी/निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव)
2	विशेष सर्वेक्षण कानूनगों	सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा +2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव (दो वर्ष का सरकारी/निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव)
3	विशेष सर्वेक्षण अमीन	सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा
4	अमीन	NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त ITI संस्थान से NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय सर्वेयर ट्रेड पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र प्राप्त योग्यताधारी की सेवाएँ अमीन के रूप में प्राप्त की जा सकेंगी।
5	विशेष सर्वेक्षण लिपिक	स्नातक
6	कार्यालय परिचारी (बाह्यस्रोत)	मैट्रिक

7. बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-7 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली, 2019 के नियम-7 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

चयन की प्रक्रिया :—

- पदों पर चयन “बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECE Board)” के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।
- चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्त के 50 प्रतिशत तक का प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। प्रतीक्षा सूची के अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा।
- चयन चालू योजना के वर्तमान योजना अवधि विस्तार तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा।”
- चयन हेतु अध्याचना विभाग द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECE Board) को उपलब्ध करायी जायेगी तथा चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा एवं प्रतीक्षा सूची प्राप्त की जायेगी।
- समय-समय पर रिक्त हुए पदों को प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जा सकेगा।

6. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECE Board) से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्यवाई हेतु नियोजन समिति का गठन निम्नवत् होगा :-

(i)	निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय बिहार, पटना	—	अध्यक्ष
(ii)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव के अन्यून स्तर के पदाधिकारी	—	सदस्य
(iii)	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित पदाधिकारी	—	सदस्य
(iv)	अल्पसंख्यक वर्ग के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी	—	सदस्य
(v)	सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	—	सदस्य सचिव

8. बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-8 के उप नियम-4 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली, 2019 के नियम-8 के उप नियम-4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(4) समाहर्ता-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी/बन्दोबस्त पदाधिकारी के प्रतिवेदन अथवा अन्य साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात् चयनित कर्मों को हटाने का अधिकार निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को होगा। वे किसी भी कर्मों को हटाने से पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए सुनने का अवसर प्रदान करेंगे। निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय द्वारा नियोजन समाप्त किये जाने पर अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के समक्ष 45 दिनों के अन्दर अपील किया जा सकेगा।”

9. बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-9 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली, 2019 के नियम-9 के निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(9) सफल चयनित अभ्यर्थियों को योगदान के पश्चात् विभाग/निदेशालय द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार जिला/राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें नियोजित कर्मियों को प्रशिक्षण प्राप्त करना एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

10. बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-9 के बाद नया उप नियम-9(1) का जोड़ा जाना।— निम्नलिखित उप नियम-9(1) उक्त नियमावली, 2019 के नियम-9 के बाद जोड़ा जाएगा :-

9 (1) नियोजित कर्मियों का मानदेय :- नियोजित कर्मियों का मानदेय सरकार द्वारा निर्धारित होगा। पारिश्रमिकी/मानदेय में यदि राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई संशोधन/परिवर्तन (वृद्धि/कमी) किया जाता है तो उक्त नियोजित कर्मियों को संशोधित/परिवर्तित (वृद्धि/कमी) मानदेय अनुमान्य किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
अपर मुख्य सचिव।

**Revenue and Land Reforms Department
(Directorate of Land Records and Survey)**

**Notification
The 23rd June 2023**

No.-01/LRS(5)Rule Amendment (Spl. Survey. Contractual Employment)-05/2022-5241—
In exercise of the powers conferred by the Special Survey and Settlement Act, 2011, the Governor of Bihar makes the following rules to amend the Bihar Special Survey Honorarium Based Contractual Employment Rules, 2019:-

1. **Short title, extent and commencement.**—These rules may be called the Bihar Special Survey Honorarium Based Contractual Employment (Amendment) Rules, 2022.
(2) It shall be extended to the whole of the state of Bihar.
(3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.
2. **Substitution of sub-rule-1 (f) and (h) of rule-3 of the Bihar Special Survey Honorarium Based Contractual Employment Rules, 2019.**— Sub rule-1(f) shall be deleted and Sub-rule-1 (h) of rule-3 of the said rules, 2019 shall be substituted by the following :-
“(h) Office Attendant (Outsourced)”
3. **Substitution of sub-rule-3 of rule 3 of the Bihar Special Survey Honorarium Based Contractual Employment Rules, 2019.**—Sub-rule-3 of rule-3 of the said rules, 2019 shall be substituted by the following :-
“(3) The services of office attendant (outsourced) can be obtained from outsourced agency and the services of data entry operator can be obtained through Beltron.
4. **Substitution of sub-rule-4 (c) of rule-3 of the Bihar Special Survey Honorarium Based Contractual Employment Rules, 2019.**—Sub-rule-4 (c) of rule-3 of the said rules, 2019 shall be substituted by the following: -
“The services of a qualified person having certificate in a two-year surveyor trade course recognized by ITI recognized by NCVT/SCVT can be obtained as Amin.”
5. **Substitution of Rule-4 of the Bihar Special Survey Honorarium Based Contractual Employment Rules, 2019.**—Rule-4 of the said Rules, 2019 shall be substituted by the following:-
“(4) The age limit for all the above posts shall be as per the norms prescribed for appointment in the State Government. Age shall be counted from the first day of January of the employment year.”
6. **Substitution of Rule-6 of the Bihar Special Survey Honorarium Based Contractual Employment Rules, 2019.**—Rule-6 of the said Rules, 2019 shall be substituted by the following:-

Minimum Education Qualification:-

Sl. No.	Designation	Qualification
1	2	3
1	Special Survey Assistant Settlement Officer	Bachelor Degree in Civil Engineering + Minimum 2 Years working Experience (2 Years working Experience in Government/ recognized Non-Government Organisation)
2	Special Survey Kanungo	Diploma in Civil Engineering + Minimum 2 Years working experience (2 Years working experience in Government/recognized Non-Government Organisation)
3	Special Survey Amin	Diploma in Civil Engineering
4	Amin	The Service of a qualified Person having certificate in two year surveyor trade course by NCVT/SCVT from ITI institute recognized by NCVT/SCVT may be obtained as Amin.
5	Special Survey Clerk	Graduate
6	Office Attendant (Outsourced)	Matric

7. Substitution of rule-7 of the Bihar Special Survey Honorarium Based Contractual Employment Rules, 2019.—Rule-7 of the said rules, 2019 shall be substituted by the following:-

1. The selection on the posts shall be done on the basis of the recommendation received on the basis of the results of the competitive examination organized by the "Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board (BCECE Board)".
2. There shall be a provision of waiting list up to 50 percent of the post wise total vacancy in the selection process. The duration of the waiting list shall be decided by the department.
3. This selection will be valid till the extension of the present plan period of the current plan. If necessary, the period will be extended.
4. The requisition for selection will be made available by the Department to the Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board (BCECE Board) and the recommendation and waiting list of the selected candidates will be obtained.
5. Vacant posts from time to time can be filled through waiting list.
6. On the basis of the recommendation received from the Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board (BCECE Board), for employment of the selected candidates, the employment committee will be constituted as follows:-

(i)	Director, Directorate of Land Records & Survey, Bihar, Patna	—	Chairman
(ii)	The Officer not below the rank of Joint Secretary, Revenue and Land Reforms Department	—	Member
(iii)	The Officer of SC/ST category nominated by the General Administrator Department, Bihar, Patna	—	Member
(iv)	The Officer of minority category of Revenue and Land Reforms Department/Nominated by the General Administrator Department, Bihar, Patna	—	Member
(v)	Assistant Director, Directorate of Land Records & Survey	—	Member-Secretary

8. Substitution of sub-rule-4 of rule-8 of the Bihar Special Survey Honorarium- Based Contractual Employment Rules, 2019.—Sub-rule-4 of rule-8 of the said rules, 2019 shall be substituted by the following:-

“(4) After being satisfied on the basis of the report of the Collector-cum-Settlement Officer/Settlement Officer or other evidence, the Director, Directorate of Land Records and Survey, Bihar, Patna will have the right to terminate the selected personnel. He will give an opportunity of hearing by following the Principle of Natural Justice before termination of any employee. On termination of employment by the Director, Land Records and Survey, an appeal can be made before the Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Revenue and Land Reforms Department within 45 days.

9. Substitution of Rule-9 of the Bihar Special Survey Honorarium Based Contractual Employment Rules, 2019.—Rule-9 of the said Rules, 2019 shall be substituted by the following:-

“(9) Successfully selected candidates will be given training at the district/ state level as per the time period fixed by the Department/ Directorate, in which it will be mandatory for the employed personnel to undergo training and pass out”.

10. Addition of new sub-rule - 9 (1) after rule-9 of the Bihar Special Survey Honorarium Based Contractual Employment Rules, 2019.—The following sub-rule-9 (1) is added after rule-9 of the said rules, 2019 :-

9 (1) Honorarium of employed personnel:- The honorarium of employed personnel shall be determined by the Government. If any amendment/ change (increase/decrease) is made in the remuneration/honorarium by the State Government/Department, then the revised/changed (increase/decrease) honorarium shall be admissible to the said employed personnel.

By order of the Governor of Bihar,
BRIJESH MEHROTRA,
Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 500-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>